28-10-26 VNS PG-6 EDITORIAL.qxd 27-10-2026 20:05 Page 1

'अर्नब' से सतर्कता

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) का मानना है कि चक्रवाती तूफान 'अर्नब' अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर तूफान है और इससे उत्तर प्रदेश, बिहार सहित नौ राज्योंपर प्रभाव पड़नेकी आशंका है। इन राज्योंमें आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी भी शामिल हैं। इसके प्रभावके प्रथम चरणमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेशमें भारी वर्षा हो सकती है। अर्नब तूफान बंगालकी खाड़ीमें तेजीसे मजबूत हो रहा है। तूफान बुधवारको आंध्रप्रदेशके तटीय क्षेत्रमें टकरानेकी आशंका है। यह तूफान ११५ से १२५ किलोमीटर प्रति घण्टेकी तेज हवा और लगभग १४० किलोमीटर प्रति घण्टेतकके झोंकेसे चल सकते हैं। आंध्रप्रदेश और दक्षिण ओडिशा सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेशके लिए भी सावधानी बरतनेकी आवश्यकता है। वैसे सभी नौ राज्योंके लिए 'अर्नब' का अलर्ट जारी कर दिया गया है। २८ से ३० अक्तूबरके दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहारमें भारी वर्षाका अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेशमें २९ अक्तूबरको बहुत भारी वर्षा सम्भव है। जहां चक्रवातका अधिक प्रभाव पड़ने वाला है वहां स्कूल-कालेज बंद कर दिये गये हैं। ओडिशाके छह जिलोंमें पर्यटनपर रोक लगा दी गयी है। सभी तटीय क्षेत्रोंमें मछली पकड़नेपर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। चक्रवाती तूफानसे निबटनेके लिए केन्द्र और राज्य सरकारोंने पूरी तैयारी कर ली है जिससे कि तूफानके प्रभावसे क्षति कम हो सके। केन्द्र और राज्य सरकारोंने सतर्कता बढ़ा दी है। केन्द्र सरकारके कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथनने प्रभावित होने वाले राज्योंमें हुई तैयारियोंकी समीक्षा भी की है। राज्योंके मुख्य सचिवोंको आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। अर्नबके खतरेको देखते हुए दक्षिणी तटीय रेलवेने ५३ ट्रेनें रद कर दी हैं और २४ घण्टे सक्रिय रहने वाले वार रूम भी बनाये गये हैं। राहत और बचावके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफकी टीमोंको तैयार रखा गया है। आश्रय स्थलोंकी भी व्यवस्था की गयी है। सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलोंको आवश्यकता पड़नेपर राहत और बचाव कार्योंमें सक्रिय रहनेके निर्देश दे दिये गये हैं। जिला प्रशासनको पूरी तरह तत्परता बरतनेका आदेश दिया गया है। आम जनताको अपने स्तरसे सभी निर्देशोंका पालन करनेकी जरूरत है। तूफानके बाद भी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि तेज हवाओंका दौर पुन: वापस आनेकी भी आशंका बनी रहती है। अर्नब तूफान बड़ी चुनौती है और इसमें किसी भी स्तरपर शिथिलता नहीं होनी चाहिए।

ग्राहकोंका शोषण अक्षम्य

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का ब्रिटानिया ब्रेडके भ्रामक विज्ञापनपर रोक और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेडपर एक लाख रुपये जुर्माना लगाना उपभोक्ताओंके हितमें महत्वपूर्ण कदम माना जायगा। भ्रामक विज्ञापनके माध्यमसे ग्राहकोंके साथ किस कदर धोखाधड़ी की जा रही थी, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि कम्पनीके उत्पाद ब्रेडमें गेहूंके आटेकी मात्रा ६२ प्रतिशत थी। शेष ३८ प्रतिशतमें चावलकी भूसी एवं अन्य सामग्री शामिल हैं जबकि विज्ञापनमें दावा किया गया कि ब्रेड शत-प्रतिशत गेहूंसे बना है, जो ग्राहकोंका शोषण है। इस तरहकी धोखाधड़ी अक्षम्य अपराध है। सीसीपीए मामलेको गम्भीरतासे लेते हुए इसी माह २२ अक्तूबरके अपने आदेशमें कम्पनीके सभी प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया समेत इण्टरनेट मीडियापर तत्काल प्रभावसे इस विज्ञापनको बन्द करनेका निर्देश दिया है। साथ ही १५ दिनके भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनेको कहा है। हालांकि कम्पनीने जांचमें यह स्वीकार किया है कि 'शत-प्रतिशत होल व्हील' ब्रेडमें गेहूंका आटा केवल ६२ प्रतिशत है लेकिन सीसीपीएने इस दलीलको यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दावा उत्पादकी गुणवत्ता बतानेके लिए था। इस सन्दर्भमें सीसीपीएका यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह दावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम २०१९ के तहत भ्रामक है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि ब्रेड पूरी तरह गेहूंसे बना है। इस तरहके विज्ञापनोंसे भ्रमकी स्थिति पैदा होती है। जब किसी उत्पादमें अन्य सामग्री मिलायी जा रही है तो उसे शत-प्रतिशत शुद्ध होनेका दावा कैसे किया जा सकता है। सीसीपीएकी ब्रिटानिया कम्पनीपर काररवाई उचित और न्यायसंगत है। साथ ही उन कम्पनियोंके लिए बड़ा सबक है जो भ्रामक विज्ञापनोंके माध्यमसे ग्राहकोंको आकर्षित करते हैं। लोगोंको भी ऐसे भ्रामक विज्ञापनोंसे बचना चाहिए।

लोक संवाद

किसे नहीं रखना चाहिए व्रत

महोदय,-करवा चौथका व्रत सुहागिन महिलाएं पतिकी लम्बी उम्र और सुखी दांपत्य जीवनकी कामनाके लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदयसे लेकर चंद्रोदयतक निर्जला व्रत करती हैं और चंद्रमाको अर्घ्य देनेके बाद व्रत खोलती हैं। इस साल करवा चौथ २९ अक्तूबर २०२६ को मनाया जायगा। हालांकि पूरे दिन बिना कुछ खाये-पिये रहना हर किसीके लिए सुरक्षित नहीं होता। खासकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और कुछ स्वास्थ्य समस्याओंसे जूझ रही महिलाओंको व्रत रखनेसे पहले अपनी सेहतका ध्यान रखना चाहिए। आइये जानते हैं किन परिस्थितियोंमें निर्जला व्रत रखनेसे बचना चाहिए। गर्भावस्थाके दौरान शरीरको पर्याप्त पोषण और तरल पदार्थोंकी जरूरत होती है। ऐसेमें लंबे समयतक बिना पानी और भोजनके रहनेसे डिहाइड्रेशन, चक्कर, कमजोरी और ब्लड शुगरमें उतार-चढ़ाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओंको निर्जला व्रत रखनेसे बचना चाहिए। यदि आप किसी धार्मिक परम्पराके कारण व्रत रखना चाहती हैं तो पहले अपने डाक्टरसे सलाह लें और सेहतको प्राथमिकता दें। जो महिलाएं छोटे बच्चोंको स्तनपान कराती हैं, उनके लिए पर्याप्त पानी, कैलोरी और पोषक तत्व लेना जरूरी है। लम्बे समयतक बिना पानी और भोजनके रहनेसे मांको कमजोरी, सिरदर्द या डिहाइड्रेशन हो सकता है। खासकर यदि बच्चा नवजात है या मांकी सेहत पहलेसे कमजोर है तो निर्जला व्रत रखनेसे बचना बेहतर है। व्रत रखनेसे पहले डाक्टरसे सलाह जरूर लें। **-मिनाली शर्मा, वाया ईमेल।**

ब्रिक्स संसदीय मंचसे शान्तिका संकल्प

आज जब विश्व युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे गम्भीर चुनौतियोंसे घिरा है, तब अंतरराष्ट्रीय सहयोग आमजनके जीवनमें सकारात्मक परिवर्तन लानेमें निहित है। ऐसे समयमें संविधान सदनमें आयोजित १२वां ब्रिक्स संसदीय मंच वैश्विक लोकतांत्रिक संवाद और बहुपक्षीय सहयोगका अवसर है।

❐ ललित गर्ग

नयी दिल्लीके संविधान सदनमें आयोजित १२वां ब्रिक्स संसदीय मंचका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि विकासका वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें सम्मान, सुरक्षा, अवसर और खुशहाली सुनिश्चित करना है। सकल घरेलू उत्पादकी वृद्धि, तकनीकी प्रगति, व्यापारका विस्तार और बुनियादी ढांचेका विकास तभी सार्थक हैं, जब उनका लाभ समाजके अंतिम व्यक्तितक पहुंचे। विकासकी चमकके बीच यदि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक वंचना बनी रहती है तो प्रगतिका दावा अधूरा है। इसलिए जन-केन्द्रित विकासकी अवधारणा आज वैश्विक नीतियोंकी अनिवार्य कसौटी बननी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाका संसदीय संवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहितको प्राथमिकता देनेपर बल इसी दृष्टिसे विशेष प्रासंगिकता रखता है। संसद लोकतंत्रकी आत्मा है। वह केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं, बल्कि जनताकी आकांक्षाओं, पीड़ाओं, अधिकारों और अपेक्षाओंकी प्रतिनिधि है। सांसदोंका दायित्व सरकारोंके निर्णयोंका समर्थन करना भर नहीं, बल्कि उनकी समीक्षा करना, जनहितके प्रश्न उठाना और सत्ताको जवाबदेह बनाये रखना भी है। जब विभिन्न देशोंके निर्वाचित प्रतिनिधि एक मंचपर बैठकर अनुभवों और विचारोंका आदान-प्रदान करते हैं, तब संसदीय लोकतंत्रकी शक्ति राष्ट्रीय सीमाओंसे आगे बढ़कर वैश्विक कल्याणका माध्यम बन सकती है। इस मंचकी प्रासंगिकता इसलिए भी बढ़ जाती है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था अनेक विरोधाभासोंसे जूझ रही है। एक ओर विज्ञान, संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ताने मानव जीवनको अभूतपूर्व क्षमताएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर युद्धों, अविश्वास, हथियारोंकी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विषमताओंने मानवताके भविष्यको अनिश्चित बनाया है। ऐसे वातावरणमें सांसदोंका साझा दायित्व है कि वे अपने-अपने देशोंकी नीतियोंको मानवीय संवेदनाओं, शांति और न्यायके व्यापक उद्देश्योंसे जोड़ें। संसदोंके बीच संवाद कार्यपालिकाकी कूटनीतिको जनप्रतिनिधियोंके अनुभवोंसे समृद्ध करता है और अंतरराष्ट्रीय निर्णयोंमें पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्वको प्रोत्साहित करता है।



यह सम्मेलन तभी ऐतिहासिक सिद्ध होगा, जब इसके विचार ठोस नीतियों, प्रभावी कानूनों और जनजीवनमें दिखने वाले परिवर्तनोंका रूप लेंगे। दुनियाको आज केवल शक्तिशाली राष्ट्रोंकी नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व, उत्तरदायी संसदों और मानवीय दृष्टिसे प्रेरित नीतियोंकी आवश्यकता है। भारतकी अध्यक्षतामें ब्रिक्स संसदीय मंच इसी दिशामें आशा जगाता है कि संवाद संघर्षोंको कम कर सकता है, सहयोग विषमताओंको घटा सकता है और लोकतंत्र विकासको मानवीय बना सकता है। यही सम्मेलनका संदेश और समावेशी तथा न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाकी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

ब्रिक्स संसदीय मंचके चार प्रमुख आधार-संस्थागत लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास-भविष्यकी वैश्विक राजनीतिके लिए विशेष महत्व रखते हैं। संस्थागत लचीलापन लोकतांत्रिक संस्थाओंको संकटोंके बीच भी सक्षम और उत्तरदायी बनायेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीकके उपयोगमें नैतिकता, पारदर्शिता तथा मानवीय हितोंकी रक्षा आवश्यक है, ताकि तकनीक सुविधाका माध्यम बने, असमानता और नियंत्रणका नहीं। इसी प्रकार सतत विकासका अर्थ आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षणके बीच संतुलन स्थापित करना है। जलवायु संकटका सामना कोई देश अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए संसाधनों, ज्ञान और उत्तरदायित्वका न्यायपूर्ण बंटवारा जरूरी है। इस सम्मेलनका एक महत्वपूर्ण पक्ष ग्लोबल साउथ अर्थात विकासशील देशोंकी आवाजको अंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियामें अधिक प्रभावशाली बनाना है। विश्वकी बड़ी आबादी इन देशोंमें निवास करती है, लेकिन वैश्विक वित्तीय व्यवस्था, व्यापारिक नियमों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओंमें उनकी अपेक्षाओंको हमेशा पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। खाद्य सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता, ऊर्जाकी सुलभता, ऋणका बोझ और विकासके लिए वित्तीय संसाधनोंकी कमी जैसी समस्याएं करोड़ों लोगोंके जीवनको प्रभावित करती हैं। ऐसेमें ब्रिक्स देशोंके सांसदोंको यह सुनिश्चित करनेका प्रयास करना चाहिए कि वैश्विक नीतियां शक्तिशाली देशोंके हितोंतक सीमित न रहें, बल्कि विकासशील समाजोंकी वास्तविक आवश्यकताओंको भी प्रतिबिंबित करें। भारतकी भूमिका इस संदर्भमें विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। भारत अपनी लोकतांत्रिक परम्पराओं, विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना, विकास संबंधी अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय सहयोगकी नीतिके माध्यमसे विभिन्न देशोंके बीच संवादका सेतु बन सकता है। भारतकी शक्ति केवल उसकी आर्थिक क्षमता या जनसंख्यामें नहीं, बल्कि विविधताओंको साथ लेकर चलने और मतभेदोंके बीच सहमति खोजनेकी लोकतांत्रिक क्षमतामें भी निहित है। नयी दिल्लीमें इस मंचका आयोजन भारतीय संसदीय कूटनीतिको नयी ऊर्जा प्रदान करता है।

भारतका प्रयास होना चाहिए कि ब्रिक्स सहयोग किसी एक देशके वर्चस्वका साधन न बने, बल्कि सभी सदस्य और साझेदार देशोंके साझा हितोंका मंच बने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाने अपने उद्घाटन संबोधनमें इस बातपर विशेष बल दिया कि ब्रिक्सकी वास्तविक सफलता संवादको ठोस परिणामोंमें बदलनेसे मापी जायगी। उन्होंने युवाओंकी आकांक्षाओंको अवसरोंसे जोड़ने तथा विकास और पर्यावरण संरक्षणको परस्पर पूरक बनानेकी आवश्यकता भी रेखांकित की। इन विचारोंमें भविष्यकी दिशा छिपी है। दुनियाकी युवा आबादीको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, रोजगार और नवाचारके अवसर उपलब्ध कराना केवल राष्ट्रीय सरकारोंका दायित्व नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोगका भी विषय है। यदि युवाओंकी ऊर्जाको सकारात्मक दिशा नहीं मिलेगी तो निराशा और असमानता सामाजिक अस्थिरताको जन्म दे सकती हैं। इसी तरह आतंकवादके विरुद्ध साझा रणनीति, अंतरराष्ट्रीय कानूनोंका सम्मान और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओंमें सुधार आजकी अपरिहार्य जरूरतें हैं। भारतने आतंकवादके विरुद्ध सहयोग और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक शासन व्यवस्थाकी आवश्यकताको संसदीय संवादके महत्वपूर्ण विषयोंके रूपमें उठाया है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओंकी विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी, जब वे सभी देशोंके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें और संकटोंके समाधानमें प्रभावी भूमिका निभायें। शांतिका अर्थ केवल युद्धका अभाव नहीं, बल्कि भयमुक्त जीवन, न्यायपूर्ण अवसर और मानवीय गरिमाकी सुरक्षा भी है।

अंतत: १२वें ब्रिक्स संसदीय मंचका वास्तविक महत्व इस बातमें निहित है कि वह दुनियाके सांसदोंको उनकी मूल जिम्मेदारीका स्मरण कराता है-वे केवल अपने देशोंकी सीमाओंके भीतर जनताके प्रतिनिधि नहीं, बल्कि साझा मानव भविष्यके निर्माणमें भागीदार भी हैं। संविधान सदनसे उठने वाला संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्रकी सार्थकता जनताके विश्वास, संस्थाओंकी जवाबदेही और नीतियोंके मानवीय परिणामोंमें है। यह सम्मेलन तभी ऐतिहासिक सिद्ध होगा, जब इसके विचार ठोस नीतियों, प्रभावी कानूनों और जनजीवनमें दिखाई देने वाले परिवर्तनोंका रूप लेंगे। दुनियाको आज केवल शक्तिशाली राष्ट्रोंकी नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व, उत्तरदायी संसदों और मानवीय दृष्टिसे प्रेरित नीतियोंकी आवश्यकता है। भारतकी अध्यक्षतामें ब्रिक्स संसदीय मंच इसी दिशामें आशा जगाता है कि संवाद संघर्षोंको कम कर सकता है, सहयोग विषमताओंको घटा सकता है और लोकतंत्र विकासको मानवीय बना सकता है। यही इस सम्मेलनका संदेश है, यही इसकी प्रासंगिकता और यही एक शांतिपूर्ण, समावेशी तथा न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाकी सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मणिपुरमें शान्तिके प्रयास

मणिपुरमें स्थायी शान्तिकी स्थापना महत्वपूर्ण विषय बना है। मई २०२३ से राज्यमें मैतेई और कुकी समुदायोंके बीच जो अविश्वासकी खाई उत्पन्न हुई है, उसने वहांके सामाजिक ताने-बानेको गहरे स्तरपर प्रभावित किया है।

❐ महेन्द्र तिवारी

मणिपुरमें मैतेई और कुकी समुदायोंके बीच जातीय हिंसाके कारण केवल सैकड़ों निर्दोष लोगोंको अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन जटिल चुनौतियोंका समाधान केवल सैन्य बल प्रयोगसे कदापि संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यापक संवाद आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाकी नितान्त आवश्यकता है। इसी सकारात्मक दिशामें एक महत्वपूर्ण कदमके रूपमें २५ अक्तूबर २०२६ को राज्यके मुख्य मंत्री युमनाम खेमचंद सिंहने कांगपोकपी जिलेमें स्थित सिनाई शिविरका सघन दौरा किया। यह दौरा कई मायनोंमें ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टिसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय समाचार माध्यमोंसे प्राप्त जानकारीके अनुसार यह पहला अवसर था जब किसी पदस्थ मुख्य मंत्रीने केन्द्र सरकार और विद्रोही गुटोंके बीच हुए बहुचर्चित अभियान निलम्बन समझौतेके अंतर्गत निर्धारित किसी शिविरका प्रत्यक्ष रूपसे निरीक्षण किया। यह विशिष्ट समझौता मुख्य रूपसे इसलिए किया गया था, ताकि सशस्त्र समूह मुख्यधारामें लौट सकें, अवैध हथियारोंका प्रयोग बंद हो और राज्यमें शांति प्रक्रियाको जमीनी स्तरपर बल मिल सके। मुख्य मंत्रीका यह साहसिक कदम यह दर्शाता है कि वर्तमान राज्य सरकार अब इन समझौतोंकी जमीनी हकीकतको परखने और सुरक्षा तंत्रमें मौजूद गम्भीर खामियोंको दूर करनेके लिए पूरी तरहसे प्रतिबद्ध है। सिनाई शिविरका यह पूरा मामला तब और भी अधिक चर्चा और चिन्ताका विषय बन गया जब एक संयुक्त सुरक्षा अभियानके पश्चात इस शिविरको पूरी तरहसे निरस्त्र कर दिया गया और इसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलने अपने सीधे नियंत्रणमें ले लिया। इस सघन सुरक्षा काररवाईके दौरान जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आये, वे राज्यकी आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली और अभियान निलंबन समझौतेके वास्तविक पालनपर कई गम्भीर प्रश्न खड़े करते हैं। जांचके दौरान वहां १७ ऐसे व्यक्ति पकड़े गये जो पंजीकृत सदस्य होनेका जाली दावा कर रहे थे और उनके पाससे फर्जी पहचान पत्र भी प्राप्त हुए। राज्यके आरक्षी अधिकारियों और खुफिया एजेंसियोंकी आरंभिक पड़तालके अनुसार, इन १७ व्यक्तियोंमेंसे ८ ने एक विशिष्ट जातीय राष्ट्रीय सेनाका सदस्य होनेका दावा किया जबकि अन्य नौ व्यक्तियोंने एक अलग मुक्ति सेनाका सदस्य होनेकी झूठी पहचान प्रस्तुत की।

इस सघन और गोपनीय अभियानके दौरान सुरक्षाबलोंने भारी मात्रामें घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की, जिसने सभीको चौंका दिया। प्राप्त विवरणके अनुसार, वहांसे २४ अत्याधुनिक आग्नेयास्त्र, ३८ कारतूस रखनेके पात्र, भारी मात्रामें मारक गोला बारूद, जानलेवा विस्फोटक और उच्च स्तरीय संचार उपकरण जब्त किये गये। हथियारोंका यह विशाल जखीरा इस बातका स्पष्ट और अकाट्य संकेत है कि अभियान निलम्बन समझौतेके तहत निर्धारित नियमोंका कहीं न कहीं घोर उल्लंघन हो रहा था। सबसे अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि इस शिविरकी कुल क्षमता १५० सदस्योंको रखनेकी थी, लेकिन वहां केवल वे १७ लोग मिले जिनकी पहचान पूरी तरहसे जाली पायी गयी। यह अनपेक्षित स्थिति प्रशासन और खुफिया एजेंसियोंके सामने यह यक्ष प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर असली पंजीकृत सदस्य कहां गये, ये जाली लोग इतनी कड़ी सुरक्षा वाले शिविरके भीतर कैसे प्रविष्ट हुए और इतनी बड़ी मात्रामें अवैध हथियार किसके संरक्षण और सहमतिसे वहां रखे गये थे। मुख्य मंत्रीने अपने दौरेके समय उपस्थित सभी शीर्ष सुरक्षा अधिकारियोंको स्पष्ट और सख्त निर्देश दिये कि किसी भी सुरक्षा अभियानके दौरान निर्दोष नागरिकोंके जीवन और उनकी संपत्तिको कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने भटके हुए युवाओं और विद्रोही गुटोंसे मार्मिक अपील की कि वे तत्काल प्रभावसे हिंसाका विनाशकारी मार्ग छोड़ें, अपने सभी अवैध हथियार प्रशासनको बिना किसी शर्तके सौंप दें और समाजकी मुख्यधारामें शामिल होकर राज्यके नवनिर्माण और विकासमें अपना बहुमूल्य योगदान दें। मुख्य मंत्रीका यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि हिंसा और प्रतिशोधकी संस्कृतिको समाप्त किये बिना मणिपुरमें स्थायी और सुदृढ़ शांतिका सपना कभी साकार नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने इस बातपर भी विशेष बल दिया कि किसी एक हिंसक घटनाके लिए पूरेके पूरे समुदायको लांछित या दंडित करना घोर अनुचित है। अपराधियोंकी पहचान उनके व्यक्तिगत कृत्योंसे होनी चाहिए, न कि उनकी जातीय या धार्मिक पहचानके आधारपर।

हालमें राज्यमें हुई तीन निर्दोष नागरिकोंकी नृशंस हत्या और सिनाई शिविरसे मिले जाली सदस्योंके मामलेको अलग अलग दृष्टिकोणसे देखने और जांचनेकी आवश्यकता है। यद्यपि ये दोनों घटनाएं राज्यकी लचर कानून व्यवस्थासे जुड़ी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूपसे इनके बीच कोई ठोस संबंध अभीतक स्थापित नहीं हुआ है। न्यायके सर्वमान्य और मूल सिद्धांतोंके अनुसार दोनों मामलोंकी बिल्कुल पृथक, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केवल पुख्ता साक्ष्यों और वैज्ञानिक तथ्योंके आधारपर ही वास्तविक दोषियोंकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें न्यायालयके माध्यमसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि भविष्यमें ऐसी अमानवीय घटनाओंकी पुनरावृत्तिको रोका जा सके। जांच एजेंसियोंको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे हर प्रकारके राजनीतिक, सामाजिक और जातीय दबावोंसे पूरी तरह मुक्त होकर अपना कार्य पूरी निष्ठाके साथ करें।मणिपुरमें शांति, सद्भाव और विश्वासकी बहालीके लिए केवल हथियारोंकी जब्ती और विद्रोही शिविरोंकी कड़ी निगरानी ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक बहुआयामी और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनानेकी नितान्त आवश्यकता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सुरक्षाबलों, विभिन्न नागरिक संघटनों और समाजके सभी वर्गोंके प्रतिनिधियोंके बीच निरन्तर, पारदर्शी और सार्थक संवाद होना चाहिए। सुरक्षा बलोंको अपनी सभी काररवाइयोंमें पूर्ण पारदर्शिता लानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मानवाधिकारोंके सख्त दायरेमें रहकर ही अपना कर्तव्य निभायें। विस्थापित परिवारोंकी उनके मूल स्थानोंपर सुरक्षित वापसी और उनका समग्र पुनर्वास इस समय प्रशासनकी सबसे बड़ी और अनिवार्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें न केवल पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, बल्कि उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास भी जगाना होगा कि वे अब अपने घरोंमें पूरी तरहसे सुरक्षित हैं।इसके अतिरिक्त प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रोंमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारके छिने हुए अवसरोंको तत्काल प्रभावसे बहाल करना भी अत्यंत आवश्यक है। जबतक युवाओंके हाथोंमें रोजगार नहीं होगा और वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षासे वंचित रहेंगे, तबतक उनके असामाजिक तत्वों द्वारा गुमराह होनेकी आशंका निरन्तर बनी रहेगी। विभिन्न समुदायोंके बीच पनपे गहरे अविश्वासकी दीवारको गिरानेके लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमोंको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और ग्राम स्तरपर शांति समितियोंका सक्रिय रूपसे गठन किया जाना चाहिए। अंतत: मणिपुरकी वास्तविक और स्थायी सफलता इसी बातमें निहित है कि वहांका प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी समुदाय, वर्ग या क्षेत्रका हो, बिना किसी भय, तनाव या आशंकाके अपना गरिमापूर्ण जीवनयापन कर सके। त्वरित और निष्पक्ष न्याय, दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी प्रशासनिक जवाबदेही और अटूट आपसी भाईचारेके माध्यमसे ही इस प्राकृतिक रूपसे खूबसूरत राज्यको पुन: स्थायी शांति और निरन्तर विकासके सुनहरे मार्गपर अग्रसर किया जा सकता है।



महाभारतमें अट्ठारहका महत्व

❐ अनुज कुमार आचार्य

भारतीय संस्कृति और सनातन परम्परामें संख्याओंका विशेष महत्व माना गया है। इनमें कुछ संख्याएं केवल गणनाका माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे गहन दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संकेत भी देती हैं। महाभारत जैसे विश्वके महानतम महाकाव्यमें बार-बार प्रकट होने वाली संख्या १८ इसी प्रकारका एक रोचक विषय है। महाभारतके अनेक प्रसंगों, संरचनाओं और घटनाओंमें अट्ठारह अंककी उपस्थिति विद्वानों, शोधकर्ताओं और अध्यात्म प्रेमियोंको सदियोंसे आकर्षित करती रही है। महाभारतका सबसे प्रसिद्ध प्रसंग कुरुक्षेत्रका युद्ध है, जो कुल १८ दिनोंतक चला। इस युद्धमें कौरवोंकी ११ अक्षौहिणी और पांडवोंकी सात अक्षौहिणी सेना सम्मिलित थी, अर्थात् कुल १८ अक्षौहिणी सेनाओंने इस महासंग्राममें भाग लिया। यह केवल संयोग नहीं माना जाता कि युद्धकी अवधि और सेनाकी कुल संख्या दोनोंमें अट्ठारह अंक उपस्थित है। युद्ध समाप्त होनेके बाद भी दोनों पक्षोंसे कुल १८ प्रमुख योद्धाओंके जीवित बचनेका उल्लेख मिलता है। कौरव पक्षसे कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा जीवित रहे, जबकि पांडव पक्षमें पांडवों सहित अन्य प्रमुख योद्धा बचे। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारतको १८ पर्वोंमें विभाजित किया गया है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व तथा स्वर्गारोहण पर्व-ये सभी मिलकर इस महान ग्रंथकी संरचना बनाते हैं। इसी प्रकार महाभारतका अमूल्य आध्यात्मिक सार कहे जाने वाले श्रीमद्भगवद्गीताके भी कुल १८ अध्याय हैं, जिनमें मानव जीवन, कर्तव्य, कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्षका अद्वितीय दर्शन प्रस्तुत किया गया है। महाभारतके युद्धके प्रमुख पात्रों और सूत्रधारोंकी संख्या भी परम्परागत रूपसे १८ मानी जाती है। इनमें धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दु:शासन, कर्ण, शकुनि, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, विदुर और भगवान श्रीकृष्ण प्रमुख हैं। इसी प्रकार युद्धमें प्रयुक्त विभिन्न सैन्य व्यूहोंकी संख्या भी १८ बतायी जाती है, जिनमें चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, वज्रव्यूह, मकरव्यूह, क्रौंचव्यूह, सर्वतोभद्रव्यूह और शकटव्यूह जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल हैं। संख्या १८ का महत्व केवल महाभारततक सीमित नहीं है। सनातन साहित्यमें १८ महापुराण और १८ उपपुराणोंका भी उल्लेख मिलता है। यह तथ्य विशेष ध्यान आकर्षित करता है कि महाभारत और पुराण-दोनोंकी रचनाका श्रेय महर्षि वेदव्यासको दिया जाता है। कुछ परम्पराओंमें यह भी माना जाता है कि महाभारतमें लगभग १८ लाख शब्द हैं, यद्यपि विभिन्न संस्करणोंमें यह संख्या भिन्न हो सकती है। महाभारतका मूल नाम 'जय' माना जाता है। संस्कृतकी पारम्परिक अंक-पद्धतियोंमें जय शब्दको भी विशेष महत्व दिया गया है। अनेक विद्वान इसे धर्मकी विजय और जीवनकी पूर्णताका प्रतीक मानते हैं। भारतीय अंक-दर्शनमें १८ का योगफल नौ होता है और नौको पूर्णता, सिद्धि तथा आध्यात्मिक उत्कर्षका अंक माना जाता है।

आधुनिक जीवनशैली और मानसिक तनावसे जीवनको खतरा

❐ डा. प्रीतम भी. गेडाम

हमारे आसपासका वातावरण ही कुछ ऐसा बन गया है कि पिछले कुछ सालोंमें जानलेवा बीमारियोंमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक तो अब रोजमर्राकी बातोंमें सुनने मिलता है, जैसे यह कोई आम बीमारी बन गयी है। आधुनिक जीवनशैली और बढ़ता मानसिक तनाव बीमारियोंको बूस्टर डोज दे रहा है, जिसके कारण निरोगी और कम उम्रका व्यक्ति भी असमय घातक बीमारियोंका शिकार होकर जान गवा रहा हैं। प्रदूषण, मिलावटखोरी, अशुद्धता, मौसमका बिगड़ता चक्र और जहरीले रसायनोंका प्रयोग वैसे ही हमें मौतके मुहानेपर पहुंचा रहा है, ऊपरसे आधुनिक जीवनशैली और मानसिक तनाव हमें शारीरिक और मानसिक रूपसे कमजोर बना रहा हैं। शरीर और मनको खुश और निरोगी रखे ऐसा वातावरण, चीजें या लोगोंका व्यवहार कम हो रहा हैं। अपनी जिम्मेदारियोंको पूरा करनेमें व्यस्त मनुष्य अपने स्वास्थ्यकी उपेक्षा करता हैं नशाखोरी, भोजनमें पोषक तत्वोंकी कमी, पैक्ड फूड-ड्रिंक, तले